मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कांग्रेसी आंदोलन की धमकी

करनाल, (म.मो.) कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करनाल के कल्पना चावला और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सिविल अस्पताल और करनाल की पीएचसी और सीएचसी में संविदा पर लगने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर ठेकेदारें की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस जल्द ही आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए। सिंह ने कहा कि ठेकेदार नौकरियां बेच रहा है। नौकरियों को लेकर स्थानीय युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा हैं। मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर लाखों रुपये लेकर नौकरियां लगाई जा रही हैं। ठेकेदार कर्मचारियों का पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा की किस्त समय पर नहीं जमा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्ति डीसी और मेडिकल कॉलेज की निगरानी में होना चाहिए। जिससे नौकरियों के लगाने में चल रही धांधलियों पर नियंत्रण लगाया जा सके।

एनसीपी का स्थापना दिवस मनाया

करनाल, (म.मो.): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने अपना 23 वां स्थापना दिवस समारोह कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी वेदपाल ने की। उन्होंने पार्टी के संस्थापक शरद पवार की कार्यशैली, कुशल सूझबूझ ओर उनकी देश व राष्ट्रहित में दूरदर्शी सोच से पदाधिकारियों को अवगत कराया। एनसीपी के प्रदेश उपप्रधान सरदार कृपाल सिंह ने कहा कि चौधरी वेदपाल ने बतौर डिप्टी स्पीकर व हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल के अध्यक्ष रहते हुए खासतौर पर उत्तरी हरियाणा के हर गाँव हर मण्डी में काम किया। उन्होंने सड़कों व पुलों का जाल बिछाया। उन्होंने हर वर्ग और समुदायों के लोगों को रोजगार दिलवाया।

रक्तदान शिविर लगाया

करनाल (म.मो.): पंकज गाबा के नेतृत्व में 49 वां ब्लड डोनेशन कैंप विर्क अस्पताल में समाजसेवी आकाश सिरस्वाल के जन्म दिवस पर लगाया गया। इस मौके पर पंकज गाबा ने कहा इस संकट की घड़ी में रक्तदान करने वाले रक्त के जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी और मौत के बीच का रोल अदा कर रहे हैं। वह मौत को पीछे धकेल रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी में इन रक्त वीरों का इस पुण्य कार्य में सहयोग करना सदैव याद रखा जाएगा। इस मौके उनके साथ सोनू शर्मा,नरेश उर्फ बल्ला नीलोखेड़ी, राजेंद्र कल्याण, प्रदीप ढिल्लों, मोनू राणा, राहुल शाहपुर,काला कमांडो,गुरलाल लाली,पीयूष आदि मौजूद रहे।

नए निगमायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा की

करनाल, (म.मो.): नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने इंजीनियरिंग विंग के साथ बैठक कर तमाम विकास कार्यों की जानकारी ली। दर्जनों विकास परियोजनाओं को लेकर एक-एक की समीक्षा की। निगमायुक्त ने सभी इंजीनियरों से कहा कि विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, सामग्री गुणवत्तायुक्त हो, हर काम के सैम्पल भरें और उन्हें चेक करवाएं। ध्यान रखा जाए कि सारा काम पारदर्शिता से हो, ऐसे सेम्पलों की अचानक क्रॉस चेकिंग की जा सकती है, खामी मिली तो सम्बंधित इंजीनियर या अधिकारी की जवाबदेही होगी। सभी बड़े प्रोजेक्टों का चार्ट अवश्य बनवाएं, ताकि उनकी प्रोग्रेस की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान को सर्वोपरि रखें।

सीजेएम ने 'अपना आशियाना' का दौरा कर जाना बेसहारा लोगों का हाल

करनाल (म.मो.) जिन्हें देख कर लोग नजरे फेर लेते है, जिन्हें बोझ समझ कर अपने भी मुंह मोड़ लेते है उन्हीं मानसिक रुप से कमजोर और बेसहारा लोगों का सहारा बना है करनाल का अपना आशियाना। इस आश्रम में कई बेसहारा लोग रहते है और यहां इनकी पूरी देखभाल की जाती है।

जुंडला गेट इंद्रा कॉलोनी में स्थित 'अपना आशियाना' आश्रम में इस वक्त करीब 112 लोग रह रहे हैं जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग है। यहां उनका इलाज भी किया जाता है और तो और कई लोग यहां से ठीक होकर भी गए है। संस्था के लोग पिछले 2 सालों से इसी नेक काम में जुटे हैं। संस्था के लोग ना सिर्फ यहां रह रहे लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते है बल्कि उन्हें वो प्यार भी देने की कोशिश करते है, जो शायद इन्हें अपने परिवार से नहीं मिला ताकि ये भी अपनी मूल्यवान जिंदगी का महत्व समझ सके। इन्हीं लाचार, बेघर और बेसहारा व्यक्तियों के हालात जानने के लिए चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल जसबीर ने अपना आशियाना आश्रम का दौरा किया और वहां का निरीक्षण कर आश्रम में रह रहे बेसहारा व्यक्तियों को भोजन भी वितरण किया। आश्रम में रह रहे लोगों का हाल चाल पूछा। आश्रम के कार्यकारिणी सदस्यों से यह भी जानना चाहा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल से अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमेशा आश्रम में रह रहे लोगों को उचित सहायता प्रदान करेगी।

मिड डे मील वर्कर्स को पड़े रोजी-रोटी के लाले

करनाल (म.मो.) मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की बैठक जिला प्रधान शिमला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष रूप से पहुंचे सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी ने कहा कि सरकार मिड डे मील वर्करों की ओर ध्यान दे। कोरोना संकट काल में मिड डे मील वर्करों पर भी बुरा असर पड़ा है। इनके परिवारों को भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। सतपाल सैनी व शिमला ने मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्करों के बाकाया वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। अभी मिड डे मील कुक को 10 महीने मानदेय मिलता है, वेतन पूरे 12 महीने का मिलना चाहिए। बकाया वर्दी भत्ता जारी किया जाए। 60 साल की आयु में वर्कर की रिटायरमेंट के बारे में हमारी मांग है कि वर्कर को 66 साल की उम्र तक काम करने की अनुमति हो। किसी भी वर्कर को काम से न हटाया जाए। मिड डे मील वर्कर को स्थाई कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।

हरियाणा में विकास की जमीनी हकीकत काछवा में देखिए

जब सीएम के इलाके का यह हाल, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा

करनाल, (म.मो.) : काछवा में ठीक गुरुद्वारे के सामने बनी बस्ती में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। यहां गरीबों को सौ-सौ गज के प्लॉट दिए गए थे। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। कॉलोनी में छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया गया था। यहां ग्राम पंचायत ने गांव का मलबा डाला तो सरकारी स्कूल बिल्डिंग खंडहर में बदल गई है। बस्ती में सीवरेज व पानी के पाइप डाले गए थे, जिसकी वजह से सारी सड़कें उखाड़ दी गई थीं। सीवरेज डालने के बाद ना तो उस कॉलोनी में सड़के बनाई गईं और ना ही साफ सफाई करवाई गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां पर रहना नर्क से भी बदतर है क्योंकि सरकार ने हमें 100 गज के प्लाट तो अलाट कर दिए लेकिन सफाई के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। गलियां उबड़ खाबड़ हैं जिसमें आधे से ज्यादा प्लॉट खाली पड़े हैं, उनमें आवारा पशु वह सूअर घूमते दिखाई देते हैं। मामूली बारिश में भी प्लॉटों में पानी खड़ा हो जाता है और गंदी बदबू आती है। जिससे यहां पर रहना बहुत मुश्किल है।

कॉलोनी वासियों का कहना है कि कोरोना व ब्लैक फंगस से तो हम बाद में मरेंगे, पहले तो हम इस बदबू व गंदगी से ही मर जाएंगे। इस बारे में गांव के सरपंच अजय कुमार से भी अपील कर चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ओएसडी अमरेंद्र सिंह जब गांव में बैठते थे तो हमने लिखित में कई बार उनको भी शिकायत दी है। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच ने भी हमारी गलियों का कोई सुधार नहीं करवाया। लोगों में सरपंच व सरकार के खिलाफ काफी रोष है। स्वच्छता अभियान को लेकर उपायुक्त और बाकी अधिकारी बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत काछवा में दिखाई देती है। पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी गांव को गंदगी से मुक्त करवाने का अभियान भी नहीं चलवाते। लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव काछवा का यह हाल है तो बाकी हरियाणा का क्या हाल होगा।

बीज बिक्री आधी, डूबने के कगार पर पहुंचीं इन्द्री की कंपनियां

बीज कंपनियां डूबीं तो किसानों पर भी पड़ेगा असर

करनाल/इन्द्री, (जेके शर्मा) कोरोना महामारी के चलते बीज उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस सीजन में करीब 50 प्रतिशत बीज की ही बिक्री हो सकी। बीज कम्पनियों की इस हालत का असर बीज उत्पादन संस्थान संचालकों के साथ-साथ किसानों पर भी पड़ेगा। बीज व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता करने के साथ बीजों पर लगने वाले टैग शुल्क समाप्त करने की मांग की।

मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में बीज व्यवसाय में इंद्री क्षेत्र बीज व्यवसाय का हब है। करीब 30 से अधिक बीज संस्थान इस क्षेत्र में बीज तैयार करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में 40 हजार से 50,000 क्विंटल बीज तैयार होता है, जो हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और अन्य राज्यों में जाता है। उत्तम खेती के लिए तैयार होने वाले हरियाणा के बीज संस्थानों का 75 प्रतिशत हिस्सा प्राइवेट बीज संस्थानों का है जबकि करीब 25 प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी नियंत्रण में है। ऐसे में प्राइवेट बीज संस्थानों पर किसानों की बीज की निर्भरता रहती है। यदि किसी कारण से बीज उद्योग आर्थिक मंदी की चपेट में फंस कर बीज संस्थान बंद होते हैं तो फिर किसानों के लिए भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यदि किसानों को उन्नत किस्म के अधिक पैदावार देने वाले बीज नहीं मिलेंगे तो फिर किसानों की उपज पर उल्टा असर होने से किसानों की आय कम हो जाएगी। आय कम होने से किसानों की आर्थिक हालात और भी खराब हो सकती है।

बीज व्यवसाय कर रहे भूपेंद्र कंबोज, ऋषि पाल कांबोज, कृष्ण काम्बोज, संजीव कुमार, मनीराम कंबोज, श्याम सिंह और धर्मपाल काम्बोज ने बताया कि इस बार बीज उद्योग पर बीज का उठाव कम होने से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते तीन सीजनों से बीज की बिक्री पर असर पड़ रहा है। इस बार तो बीज की बिक्री 50 प्रतिशत तक ही हो पाई है। ऐसे में बीज कम्पनियों के पास बीज बच जाने से बीज संस्थान संचालकों को खुले बाजार में बचा हुआ बीज कम रेट पर बेचने पर

विवश होना पड़ता है। यदि वह कम रेट पर बीज खुले बाजार में नहीं बेचते तो अगले सीजन तक उनके बीज कबाड़ में डालने पड़ेंगे।

इन बीज संचालकों का कहना है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों से बीज की फसल प्राप्त करते हैं। उस पर रख रखाव और दवाई इत्यादि अन्य प्रोसेसिंग खर्च आता है। ब्याज इत्यादि के खर्चे जोड़कर बीज को सुरक्षित रखकर खरीद केंद्रों तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि बीज संचालकों को बीज सुरक्षित रख कर बेचने तक के खर्चे लगाकर यदि फायदा नहीं मिलता तो फिर बीज संचालक आर्थिक मंदी की चपेट में फंस जाते हैं।

बीज संस्थानों के संचालकों पर किसान आंदोलन का भी प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बीज संस्थान संचालक बीजों की मांग पर और कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन का अधिक प्रभाव मान रहे हैं। लेकिन बीजों की मांग कम होने का सही सही कारण का अंदाजा वह भी नहीं लगा पा रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार बीज संस्थानों को सब्सिडी दे और सर्टिफाइड बीजों के नाम से लगने वाले टैग शुल्क को सिर्फ बिक्री होने वाले बीजों पर ही ले। बैंकों से लिए गए कर्जे की ब्याज माफी भी की जाए। बीज संस्थानों के संचालकों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की व्यवस्था नहीं की तो फिर बीज संस्थानों का बंद होना तय है। इस बारे में खंड कृषि अधिकारी डॉ अश्वनी कंबोज ने बताया कि इस बार बीज कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ा है। इस हालत का असर किसानों पर पड़ सकता है। बीज कंपनियों को बचाने के प्रयास होने चाहिए।

खेत मजदूर यूनियन का प्रदर्शन

करनाल, (म.मो.) अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से सरकार द्वारा खाद्य तेल बंद करने का निर्णय न केवल नीतिगत रूप से जनविरोधी है, बल्कि अमानवीय एवं भारतीय संविधान की कल्याणकारी भावना व नागरिक के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के भी खिलाफ है। यूनियन के राज्य प्रधान जगमाल सिंह ने कहा कि पीडीएस के तहत खाद्य सरसों तेल की आपूर्ति निर्बाध रूप से लगातार जारी की जाए। तमाम गरीब भूमिहीन परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जाए। कोरोना महामारी के चलते तमाम परिवारों को बिना शर्त राशन वितरण किया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शीशपाल, पाल सिंह व सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी मौजूद रहे।